(1)	(2)	(3)	(4)
मध्य प्रदेश			
सिहोर			
फ़रवरी, 16–17	8	100.00	2.33 इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने दंगा पीड़ित व्यक्तियों के लिये एक राहत शिविर स्थापित किया
महाराष्ट्र			
नासिक			
मई, 10	8	43.05	3.72
पनवल			
मई, 10	2	66.48	उ.न.
उत्तर प्रदेश			
मेरठ			
फ़रवरी, 26	2	7.42	1.00
नियोरिया (पीली भीत)			
मार्च, 26–27	26	—	5.47
इलाहाबाद			
जून, 14–18	9	2.65	उ.न.

देश में टेलीविजन उद्योग

245. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीविजन उद्योग की क्या स्थिति है और यह देश की ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टेलीविजन सैटों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कहां तक सक्षम है ;

(ख) सरकार ने ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टेलीविजन आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की है ; और

(ग) भारतीय ट्रांजिस्टर रेडियो उद्योग को जापान तथा विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सक्षम बनाने हेतु सरकार की नीति और कार्यक्रम क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० आर० के नारायण) :

(क) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सैटों को विनिर्माण मख्यत: स्वदेशी संघटक पूर्जों पर ही आधारित है जहां तक

रंगीन दूरदर्शन सैटों का संबंध है, इन्हें वर्ष 1982 में शूरू किया गया। इनके सघंटक पुर्जे मुख्यत: आयात किए जा रहे हैं। किन्तु, उद्योग में रंगीन दूरदर्शन के लिए सघंटक पूर्जों का विनिर्माण करना शुरू कर दिया है और वर्ष 1989 के आरंभ तक इनका काफी हद तक स्वदेशीकरण कर लिया जाएगा। देश की मांग को पूरा करने के लिए देश में हो रहे दूरदर्शन सैटों का उत्पादन पर्याप्त है।

(ख) स्वदेशी उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी उद्योग, (जिसमें दूरदर्शन तथा रेडियो शामिल हैं), को बढ़ावा देने के लिए तथा इन उत्पादों की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. व्यवहार्य उत्पादन क्षमता के लिये औद्योगिक अनुमोदन उदारतापूर्वक जारी करना ताकि कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले।

2. एक ही लाईसेंस के अन्तर्गत कई उत्पादों के विनिर्माण का लाइसेंस जारी करना।

3. इलेक्ट्रानिक संघटक–पुर्जा उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया है, जिसमें एकाधिकार प्रतिबन्धकारी व्यापार पद्धात के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां शामिल हैं, तथा इस क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनमति उदारतापूर्वक दी जाती है।

4. दिनांक 16 जून, 1986 को हाल में सरकार द्वारा घोषित एक मुश्त वित्तीय रियायतों के लिए, समूचे इलेक्ट्रानिक्स संघटक पुर्जा उद्योग द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली खपत योग्य वस्तुओं तथा कच्ची सामग्री और उनके अलग अलग कल पुर्जों के रेंज के लिए, आयात शुल्क के ढांचे को तर्कसंगत बना दिया गया था इस उपाय के फलस्वरूप वाजिब कीमतों पर स्वदेशी संघटक पुर्जे उपलब्ध कराने में काफी सहायता मिलेगी।

5. रेडियों रिसीवरों तथा दूरदर्शन पर लगने वाले वार्षिक लाइसेंस शल्क को समाप्त करना और उसके बदले दूरदर्शन सैटों के मामले में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में एक बार में ही 100/– रु०. प्रति सैट प्रभारित करना।

6. रेडियो तथा दूरदर्शन सैटों की बिक्री के लिए विक्रेताओं द्वारा रखे जाने वाले स्वत्व लाइसेंस को समाप्त करना।

7. दूरदर्शन सैटों के विनिर्माण की प्रगति की समीक्षा करने तथा उस पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त दूरदर्शन समन्वय समिति कार्य कर रही है, जिसमें भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

8. इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैकनोलाजी डेवलप कारपोरेशन (ई.टी.एण्ड टी.) नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम.टी.बी. नामक अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत उचित लागत पर बढ़िया क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से उद्योग को थोक मात्रा में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति करके और साथ-साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) रेडियो उद्योग इस समय मख्यत: घरेलू मांग को पूरा करने में लगा हुआ है और अधिकांश उत्पादन इकाइयों प्रौद्योगिकी को समय-समय पर अद्यतन बनाने में समर्थ नहीं हैं। किन्तु सरकार की प्रगतिशील नीतियों से रेडियो उद्योग को तेजी से बढ़ावा मिलने की आशा की जाती है।